भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध (Indo-Pak. relation)

दक्षिण एशिया में स्थित भारत एक सम्य विश्व के प्रभावशाली देशों में एक है। इसके उत्तर में नेपाल तथा पर्वत राज हिमालय और दक्षिण में विशाल हिन्द महासागर। भौगोलिक रूप से यह जल और थल दोनों से जुड़ा हुआ है। इसके आकार तथा शांतिपूर्ण छवि के कारण एशिया महाद्वीप में इसका स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जबकि भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश उत्तर-पश्चिम में स्थित पाकिस्तान है। 1947 से पूर्व भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही राष्ट्र था और विदेशियों के चंगुल में अधीन था। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में कुछ स्वार्थी और सत्तालोभी राजनीतिज्ञों ने 'दो राष्ट्र' की विचार-धारा को बल दिया, जिसके कारण भारत को आजादी के साथ विभाजन भी स्वीकार करना पड़ा। ब्रिटिश नीति के अन्तर्गत भारत विभाजन की योजना के अनुपालन में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। जिस प्रकार पैतृक सम्पति के बँटवारे के बाद दो भाइयों में विवाद जारी रहता है, ठीक उसी प्रकार विभाजन के बाद भी दोनों देशों के सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे हैं और कश्मीर विवाद के कारण तनाव आज भी है। नैतिक और संतुलित दृष्टिकोण से देखा जाए तो कश्मीर के राजा हरि सिंह द्वारा भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद कश्मीर भारत का अखंड अंग बन चुका है, परन्तु पाकिस्तान उसे मुस्लिम बहुल राज्य बताकर बार-बार उस पर अपना दावा करता है और समय-समय पर उसपर अधिकार करने की कोशिशें भी करता रहता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। 05 अगस्त 2019 को धारा 370 एवं 35-A हटाने के प्रस्ताव राज्य सभा में पारित हुआ, और 06 अगस्त 2019 को लोकसभा से पारित हुआ। जम्मू कश्मीर दो भागों में बँट गया (I) जम्मू और (II) लद्दाख दो केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में उभरकर आया।

पाकिस्तान ने 22 Oct 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान की शर्मनाक पराजय हुई। पाकिस्तान के जन्म के साथ ही निम्नलिखित समस्या उत्पन्न हो गई :- (I) कश्मीर विवाद (II) हैदराबाद विवाद (III) जूनागढ़ विवाद (IV) शरणार्थियों का प्रश्न (V) ऋण अदायगी का प्रश्न (VI) नहरी पानी विवाद।

पाकिस्तान ने तोड़-फोड़, जासूसी, सीमा का अतिक्रमण के अलावा 1947, 1965, 1971 में भारत पर आक्रमण किया। फिर भी भारत ने पाकिस्तान के साथ सदैव दोस्ती और सहयोग की नीति को बरकरार रखने का प्रयास किया। वार्ता के माध्यम

से पारस्परिक समस्याओं के समाधान में [illegible]
तथा शिमला समझौता (1972) इसके ज्वलंत प्रमाण है। 1948 तक जूनागढ़ और हैदराबाद का भारत में विलय हो गया और ये प्रश्न समाप्त हो गए। पाकिस्तान को 5 वर्ष में 300 करोड़ रुपये का कर्ज भारत को चुकाना था, किन्तु पाकिस्तान ने नहीं चुकाया। विभाजन के बाद विस्थापितों की संपत्ति तथा अल्पसंख्यकों की रक्षा का प्रश्न महत्वपूर्ण था। विस्थापितों की सम्पत्ति के संबंध में पाकिस्तान ने भारत के प्रत्येक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अप्रैल 1950 में साम्प्रदायिक उपद्रवों को रोकने तथा अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से भारत-पाक प्रधानमंत्रियों के बीच नेहरू लियाकत समझौता हुआ लेकिन पाकिस्तान ने इस समझौते का भी पालन नहीं किया और पाकिस्तान से पीड़ित हिन्दू शरणार्थियों का भारत में आना जारी रहा।

दोनों देशों के मध्य एक अन्य समस्या पानी को लेकर थी। पंजाब के विभाजन के चलते रावी, सतलज और व्यास नदियों का उद्गम भारत में रह गया। इससे निकलने वाली 25 में से 20 नहरें भारत में आईं। झेलम और चेनाब मुख्यतः पाकिस्तान में बहती है। यदि भारत चाहता तो इन नदियों के पानी को रोककर पश्चिमी पाकिस्तान को मरुस्थल में बदल सकता था। 19 Sep 1960 को भारत-पाक में सिंधु बेसिन के पानी को दोनों राष्ट्रों में समान बँटवारा के प्रश्न पर नहरी पानी समझौता (सिंधु जल) हुआ।

13 Dec 2001 को भारतीय संसद पर तथा 26 नवम्बर 2008 को मुम्बई में ताज होटल व अन्य स्थानों पर हुए आतंकवादी हमले पाकिस्तान की कुटिल छवि को दर्शाते हैं। पाकिस्तान के शत्रुता का जवाब भारत ने मित्रता में दिया है। फरवरी 1999 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐतिहासिक बस सेवा के माध्यम से मित्रता की पहल की, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी विश्वासघात करके मई-जुलाई 1999 में भारत के कारगिल क्षेत्र पर हमला बोल दिया। कारगिल की इस लड़ाई में पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई, लेकिन पाकिस्तान तो बेशर्म है उसे शर्म-बेशर्म का फर्क भला समझ में आता कहाँ है।

भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की ओर से 20 जून 2004 को परमाणु परीक्षणों पर रोक जारी रखने पर सहमति बनी। पाकिस्तान के विदेश सचिव 'रियाज खोखर' एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ भारत आए। प्रथम बार पाकिस्तान ने इस मसौदे में शिमला समझौता लागू करने का निर्णय किया। जिसके प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है -

(i) भारत-पाक उच्चायोगों में स्टाफ की संख्या शीघ्र बढ़ाकर 110-110 की जाय।
(ii) कराँची और मुम्बई में दोनों देशों के वाणिज्य दूतावास खोले जाएँगे।
(iii) हिरासत में बंद मछुआरों की रिहाई की जाए।
(iv) मिसाइल परीक्षण के पूर्व सूचना दी जाए।
(v) सियाचीन, वूलर, बराज, तुलबुल नौकासंचालन परियोजना, आतंकवाद और मादक वस्तुओं की तस्करी, आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग तथा विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण विचार विमर्श में बढ़ोत्तरी पर वार्ता की जाए।
(vi) शांति और सुरक्षा का स्थायी वातावरण बनाने, एक दूसरे की परमाणु क्षमताओं को मान्यता दे

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

सामरिक स्थिरता की ओर काम करने जैसी जरूरतों के बारे में 20 जून 2004 को जारी संयुक्त बयान की दोनों देशों ने पुष्टि की।

(ग) परस्पर विश्वास उत्पन्न करने वाले उपायों पर व्यापक वार्ता का दोनों पक्षों ने प्रस्ताव किया। इसका उद्देश्य विवाद, तनाव तथा निगरानी निरीक्षा को आगे बढ़ाना था।

सियाचीन पर भारत ने 1984 में अपना कब्जा जमाया था और वहाँ से फौज हटाने को लेकर 1988-89 में राजीव गाँधी और बेनजीर भुट्टो के बीच (फौज हटाने का) निर्णय लिया गया था। 16 फरवरी 2005 को दोनों देश नियंत्रण रेखा के आर-पार एक और बस सेवा प्रारंभ करने को सहमत हुए। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तथा पाक अधिकृत कश्मीर (POK) की राजधानी मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा 7 अप्रैल 2005 से प्रारंभ हुई। श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम से 21 यात्रियों से भरी दो बसों को झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने रवाना किया। कारवाँ-ए-अमन नाम की यह बस नियंत्रण रेखा तक इन यात्रियों को लेकर गई। यहाँ बने शांति पुल (अमन सेतु) को इन यात्रियों ने पैदल पार किया। अमन सेतु की दूसरी ओर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में खड़ी बस उन्हें आगे की यात्रा पर मुजफ्फराबाद ले गई।

उधर मुजफ्फराबाद से 30 यात्रियों से भरी एक बस को पाक अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत की बस में सवार होकर श्रीनगर तक ये यात्री आए। दुख्य फेरा अप्रैल 2005 को सम्पन्न हुआ। श्रीनगर मुजफ्फराबाद के मध्य बस सेवा का संचालन भारत-पाक संबंधों के बीच एक नया अध्याय हुआ। इसके लिए अंतिम सहमति भारतीय विदेश मंत्री नटवर सिंह ने की। इन्होंने पाकिस्तानी विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी के अतिरिक्त राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से भी मिले तथा दोनों देशों के बीच कुल 6 मुद्दों पर सहमति बनी, जिसमें अमृतसर लाहौर बस सेवा प्रारंभ करने, खोखरापार मुनाबाओ रेल संपर्क बहाल करने तथा कराची एवं मुम्बई में पारस्परिक वाणिज्य दूतावास (Consulates) स्थापित करने के मुद्दे शामिल थे।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने 16-18 अप्रैल 2005 तक भारत की यात्रा की। जिसमें भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच, भारतीय नेताओं से बातचीत एवं द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करना था। आगरा में सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी पुस्तक 'The line of fire' में कारगिल से लेकर आगरा तक के यात्रा के खुलासे भी असफलता (शिखर वार्ता) के तमाम खुलासे किए हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने [illegible] असफलता का श्रेय मुशर्रफ को ही है उनके अड़ियल [illegible] नतीजे पर नहीं पहुँच सकी थी।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

वार्ता के दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ कश्मीर में आतंकवाद ...
वहाँ पर जारी खून-खराबे को 'लोगों की आजादी की लड़ाई (People battle for
freedom) कहते रहे। Terrorism मानने को कतई तैयार नहीं थे।

भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा सड़क मार्ग 20 जनवरी 2006 को
खुला जो अमृतसर से लाहौर के बीच प्रारंभ हुई। बस सेवा का प्रारंभ भारत और
पाकिस्तान के लिए 6 (छठा) मार्ग था जिसमें चार सड़क तथा दो रेलमार्ग। इससे पूर्व
दिल्ली लाहौर के बीच सदा-ए-सरहद तथा श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच समझौता
एक्सप्रेस रेलगाड़ी की भी शुरुआत हुई। अटारी-लाहौर समझौता एक्सप्रेस के बाद
दूसरी रेलगाड़ी थार एक्सप्रेस का परिचालन 18 फरवरी 2006 से शुरू हुआ।

14 July 2006 को मुम्बई में ट्रेन में विस्फोट हुआ, जिसमें 200 से
ज्यादा लोग मारे गए। डॉ० मनमोहन सिंह ने परवेज मुशर्रफ से साफ कहा कि
यदि पाकिस्तान सीमा पार के आतंकवाद रोकने के लिए कदम नहीं उठाता है तो भारत के
लिए पुनः शांति प्रक्रिया प्रारंभ करना मुश्किल होगा। फरवरी 2007 में भारत और
पाकिस्तान दोनों ने परमाणु हथियार के दुर्घटनावश इस्तेमाल की जोखिम में कमी
लाने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। 27 Dec 2007 को पाकिस्तान की प्रधानमंत्री
बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गयी। 25 मार्च 2008 को लोकतांत्रिक तरीके से
निर्वाचित 'सैय्यद यूसुफ रजा गिलानी' प्रधानमंत्री की बागडोर संभाली।

26 नवम्बर 2008 को मुम्बई पर हुए आतंकवादी हमलों में 179 लोग
मारे गए। मुंबई में पाक पोषित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ होने
का पक्का सबूत होने से दोनों देशों में काफी कटुता आ गई। प्रधानमंत्री मनमोहन
सिंह ने एक बार फिर स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को सुधर जाने की चेतावनी दी।
11 Dec 2008 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक कमेटी ने पाकिस्तान से संचालित
लश्कर-ए-तैयबा के चार शीर्ष आतंकवादी संगठनों और लश्कर के नए चेहरे के रूप
में उभरे जमात-उद-दावा को प्रतिबन्धित कर दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया
बाधित होती है तो इसका फायदा आतंकवादियों को मिलेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता 24
जून 2010 को इस्लामाबाद में हुई। जिसमें भारतीय विदेश सचिव निरुपमा राव
और पाकिस्तानी विदेश सचिव सलमान बशीर ने इस वार्ता को मैत्रीपूर्ण और रचना-
त्मक बताते हुए कहा कि सभी मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की गई। 16 जुलाई 20..
को भारतीय विदेश मंत्री एस० एम० कृष्णा एवं पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद
कुरैशी के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी लेकिन सार्थक परिणाम नहीं निकला
जिससे दोनों देशों की बीच की दूरी और बढ़ गई।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

पाकिस्तान द्वारा बार-बार नियंत्रण रेखा का उल्लंघन तथा भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के संबंध में कटुता आज भी बनी हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन से ही भारत पाक संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं रहे है। जिसके चलते ही आज चीन के आक्रामक तेवर में वृद्धि हुई है और वह अरुणाचल प्रदेश तथा कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। 9 सितम्बर 2013 को ममनून हुसैन ने, जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घनिष्ठ सहयोगी रहे है, पाकिस्तान के नये राष्ट्रपति के रूप मे कार्यभार संभाला, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में कोई सुधार नहीं हुआ / जनवरी 2013 में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर फायरिंग करते हुए भारत के दो जवानों को भून डाला और उनमें से एक का सिर तक गायब कर दिया। इस घटना की पूरे विश्व में निन्दा की गई | वर्ष 2016 मे पठानकोट पर एयरबेस की हमला, उड़ी सेक्टर में हुआ हमला प्रमुख है। इतना ही नहीं बार-बार पाक द्वारा सीजफायर उल्लंघन की घटना सामने आती रहती है। मजबूरन भारतीय सैनिकों ने वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके बावजूद आतंकी गतिविधियाँ जारी रही है / 2017 में 200 से अधिक आतंकी जम्मू-कश्मीर में मारे गए। इतना ही नहीं 'अमरनाथ की यात्रा के दौरान भी वर्ष 2017 में आतंकी हमले हुए जिसमें पाकिस्तान को ही दोषी बनाया गया, और आज भी बरकरार है

नरेन्द्र मोदी जब दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटा कर धारा 370, 35A के तहत दो केन्द्र शासित प्रदेशो में विभाजित कर दिया जिसमें जम्मू एवं लद्दाख के रूप में दो नये केन्द्र शासित प्रदेशों का जन्म हुआ। जिसकी स्वीकृति 05 अगस्त 2019 को राज्य सभा तथा 06 अगस्त 2019 को लोकसभा से मिल सदियों से चला आ रहा विवाद क्षण भर में समाप्त हो गया लेकिन कहा गया है कि दुनिया सुधर जाये, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। निष्कर्षतः आतंक का केन्द्र बना पाकिस्तान अपनी गतिविधि पर कायम है, क्योंकि कूटनीतिज्ञों का शह जब तक पाकिस्तान को पूर्णतः खोखला नहीं कर देता है तब तक बात समझ से परे है।

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष-राजनीति विज्ञान
डी. के. कॉलेज, डुमरॉव
दिनांक - 15/05/2020

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA